IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति एवम् व्यवसायिक ि”ाक्षा

डॉ0 मोहम्मद उस्मान
एसोसिएट प्रोफेसर
किसान पी0जी0 कॉलेज, बहराइच

- राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति 2020
- वै”वीकरण
- समवर्ती सूची
- सकल नामांकन दर
- राश्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
- NPE 2020

समय के अनुसार ि”ाक्षा के तरीकों और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन आव”यक होते है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले 34 सालों से चली आ रही ि”ाक्षा नीति में बदलाव करते हुए राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति 2020 दे दी है। बदलते वि”व और वै”वीकरण के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए ऐसे परिवर्तनों और सुधारों की आव”यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ि”ाक्षा नीति दे”ा और समाज का आने वाला कल कैसा होगया ये निर्धारित करने में अहम् भूमिका निभाती है। यह नीति स्कूली ि”ाक्षा से लेकर उच्च ि”ाक्षा तक के सभी प्रकार सुधारों पर ध्यान आकर्शित करती है। राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति–2020 में उच्च ि”ाक्षा से सम्बंधित अनेक परिवर्तनों और सुधारों को सुझाया गया है। अब महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि ि”ाक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें इसे लागू कैसे करती है। चूंकि ि”ाक्षा समवर्ती सूची का विशय है अतः राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति को लागू करने में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों से ऐसा प्रतीत अव”य हो रहा है कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकेगा और सही मायनों में ि”ाक्षा के क्षेत्र में भारत एक नया मुकाम हासिल करेगा। इसी ि”ाक्षा नीति में उच्च ि”ाक्षा के क्षेत्र में अहम बदलावों को इस लेख में इंगित किया गया है। कई बार यह प्र”न उठाया जाता है कि छात्रों को अपने विशय मात्र के अलावा उनके आस–पास के मुद्दों, जरूरतों की कोई जानकारी नहीं है ऐसे में सरकार का सुझाव ऐसे संस्थान बनाना है जो अन्ततः अनु”ाासनात्मक होंगे। इसका मुख्य उद्दे”य व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक,

भावनात्मक, भाारीरिक क्षमताओं को विकसित किया जाना है। व्यक्ति के समग्र विकास के लिए कौ"ाल एवं मूल्यपरक ि"ाक्षा पर जोर दिया गया है। छात्रों के अपने स्थानीय निकायों, कलाकारों, भाोधार्थियों और ि"ाक्षकों के साथ अपने या किसी दूसरे ि"ाक्षण संस्थान में प्रि"ाक्षु के रूप में कार्य करने और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें रोजगार में भी फायदा मिलेगा।

यदि उच्च ि"ाक्षा के आंकड़ों को देखें तो आज दे"ा का बड़ा तबका कई कारणों से इससे वंचित है। उच्च ि"ाक्षा को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हर जिले या उसके आसपास कम से कम एक उच्च ि"ाक्षा संस्थान बनाये जाने का सुझाव दिया गया है ताकि सकल नामांकन दर जो कि 2018 में 26.30 प्रति"ात थी उसे 2035 तक 50 प्रति"ात तक बढ़ाया जा सके। उच्च ि"ाक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कई आधारभूत बदलाव किये गये है। अभी तक की व्यवस्था में छात्र यदि किसी कारणव"ा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देता है तो उसे किसी प्रकार की डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते है। राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति 2020 में इसके लिए अनेक सुझाव दिये गए है। यदि कोई छात्र एक वर्श की पढ़ाई के बाद स्नातक छोड़ना चाहे तो उसे डिप्लोमा और तीन वर्श पूरे करने पर स्नातक की डिग्री दी जायेगी। इस प्रकार की निकास व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा ऐसे छात्रों को होगा जो व्यावसायिक ि"ाक्षा, तकनीकी ि"ाक्षा एवं विदे"ाी भाशाओं से जुड़े है। चूंकि इन क्षेत्रों में कई प्रकार के रोजगार सार्टीफिकेट या डिप्लोमा स्तर के प्रमाण पत्रों से मिल जाता है। यहाँ तक एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि जो छात्र चार साल की स्नातक करना चाहते है वे स्नातकोत्तर एक साल में ही कर पायेंगें।

इस नीति में M.Phil को हटाया गया है। M.Phil की अवधि किसी वि"वविद्यालय में 2 वर्श है तो किसी में एक वर्श। ऐसे में ये कहा जाता रहा है कि इतने कम समय में अच्छे भाोध की गुजाइ"ा कम ही होती है। इसके उलट कुछ लोग यह भी मानते है कि इससे भाोध पर ही असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जान लेना आव"यक है कि चार साल की स्नातक का बी0ए0 भाोध के साथ दिये जाने की बात कही गयी है। अतः स्पश्ट है कि ऐसे छात्रों की भाोध कार्य करना होगा। अभी तक यह कार्य स्नातकोत्तर के बाद किये जाते थे। यद्यपि इस पर और अधिक स्पश्टता इसके पाठ्यक्रम बनने एवं लागू होने पर ही आयेगी।

छात्रों के बीच संवाद एवं रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के साहित्यिक, सांस्कृतिक समूह एवं वि"ोश क्लब बनाये जायेंगें। इसमें ि"क्षकों की भूमिका मार्गद"र्क की रहेगी। मेरा मानना है कि इस प्रकार के समूह छात्रों के बीच सहयोग, वाद– संवाद की भारतीय परंपरा को तो आगे बढ़ायेंगें ही साथ में ऐसे छात्र जो अपने विचार को बड़े मंचों पर या अधिक लोगो के सामने बोलने में असहज महसूस करते है उनके भीतर अपनी बात को तथ्यपरक तरीके से समझाने और कहने का आत्मवि"वास भी पैदा करेगा।

ऐसे छात्र जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नही कर पाते है इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ि"क्षण संस्थानों को पर्याप्त धनरा"ि दी जाने की वकालत भी इस नीति में की गयी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति की आव"यकता को देखते हुए राश्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक आर्थिक मदद प्रदान की जा सके इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए निजी उच्च ि"क्षण संस्थानों को भी छात्रवृत्ति देने को कहा गया है। हालांकि इसे लागू कर पाना कितना आसान होगा ये कहना अभी मु"्कल है। लेकिन सरकार की ओर से इस क्षेत्र में उठाये गये कदम सराहनीय है। चूंकि इन वर्गों के विद्यार्थियों के नामांकन में भारी गिरावट देखने को मिलती है।

ि"क्षा और भाोध को वि"वस्तरीय बनायें जाने की चर्चा हमे"ा से रही है। अब पी–एच0डी0 के दौरान छात्रों को ऐसे विशयों के क्रेडिट कोर्स करने होंगे जो उन्हें भौक्षणिक गतिविधियों में परिपक्व बनायें। इन छात्रों को ि"क्षक सहायक के रूप में भी पढ़ाना होगा ताकि ये बेहतरीन ि"क्षक बन सके। भाोध और अनुसंधान के महत्व को समझते हुए सरकार राश्ट्रीय भाोध संस्थान बनायेगी ताकि भाोधार्थियों को आव"यक आर्थिक सहायता मिल सके। जो वि"वविद्यालय अच्छा प्रद"र्न करेंगे उन्हें विदे"ाों में अपनी भाखा खोलने की अनुमति दी जायेगी। वि"व की सौ उच्च स्तरीय ि"क्षण संस्थाओं को भारत में अपनी भाखा खोलने की इजाजत भी मिलेगी। हालांकि इनके संचालन के तरीके क्या होंगें ये तो विस्तृत नियमों के आने के बाद ही साफ हो पायेगा। विदे"ाी वि"वविद्यालयों में नियमानुसार जो छात्र क्रेडिट पूरे करेंगें उनके ये क्रेडिट भारतीय वि"वविद्यालयों में मान्य होंगे।

वि”वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह भारत का उच्च ि”ाक्षा आयोग बनेगा। इनके अंतर्गत अनेकों विभाग होंगे जैसे राश्ट्रीय उच्चतर ि”ाक्षा नियामक परिशद सभी उच्च ि”ाक्षण संस्थाओं (कानून एंव मेडिकल को छोड़कर) के लिए नियामक संस्था होगी। साथ ही पारद”िर्ता बनायें रखने के लिए संस्थाओं को अपनी जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी होगी। सभी संस्थाए विनियमन (NHERC) प्रत्यापन (NAC) निधिकरण (HRGC) और अकादमिक मानक सेटिंग (GEC) पारद”िर्ता से काम कर सके इसके लिए तकनीकों के माध्यम से कामकाज को बढ़ावा दिये जाने पर भी जोर दिया गया है।

उच्च ि”ाक्षा में नामांकन अनुपात भारत में आज तक बहुत कम है ऐसे में ि”ाक्षा का निजीकरण बेहद नुकसानदायी होगा। अतः सरकार ने इस दि”ाा में उचित सुझाव दिये है। हालांकि ये किसी प्रकार काम करेगी ये तो नीति के व्यावहारिक तरीके से लागू होने के बाद ही पता चलेगा। पिछली ि”ाक्षा नीतियों में भी ि”ाक्षा पर अधिक खर्च की सिफारि”ाों के बावजूद अभी तक ि”ाक्षा पर भारत में विकसित दे”ाों की तुलना में काफी कम खर्च किया जाता रहा है जोकि सकल घरेलू उत्पाद के 44 पति”ात के लगभग है इस राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति में इसे 6 प्रति”ात किये जाने का प्रस्ताव है। सरकार इस ओर सकरात्मक दृश्टिकोण भी दिखा रही है। ि”ाक्षा के क्षेत्र में यदि प्रस्तावित 6 प्रति”ात को खर्च किया जाता है तो भारत की ि”ाक्षा के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम होगा लेकिन ि”ाक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को यह भी ध्यान रखना होगा और सुनि”चत करना होगा कि ये नीति चरणबद्ध तरीके से समय पर चालू हों।

एक आधुनिक ि”ाक्षक का कार्य जंगलों को काटना नहीं बल्कि रेगिस्तान को सींचना है। सी0एस0 लेविस

आकड़े जानकारी नहीं है, जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझ नही है, बुद्धिमानी नहीं है। क्लिफोर्ड स्टील

संदर्भ ग्रंथः

हिंदीः

1. गैंड, डी.एन. तथा भार्मा, आर.पी. ‘‘”ौक्षिक एवं माध्यमिक ि”ाक्षालय व्यवस्था राम प्रसाद का विकास एवं समस्याएं’’, रस्तोगी पब्लिके”ान, ि”ावाजी रोड, मेरठ
2. ने”ानल पॉलिसी ऑफ एजुके”ान (1986), मिनिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली–1996
3. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ NEP_ Final_Hindi_0.pdf
4. Agarwal,P.(2007).Higher education in India: Growth, concerns and change agenda. Higher Education Quarterly,61(2), 197-207.
5. Altbach, P.G. (2009), One-third of the globle:The future of higher education in china and India. Prospects,39(1),11.